

जब कोई विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर होता है तो उसकी सुरक्षा केवल मशीन पर नहीं, बल्कि पायलट के मन और साहस पर टिकी होती है। हाल ही में एक भारतीय कैप्टन ने ऐसा ही साहस दिखाया है। तेल अवीव जा रहा विमान जब बीच आकाश में था, तभी कॉकपिट के भीतर एक अप्रत्याशित और हिंसक स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है, लेकिन उस कैप्टन ने अपने घायल होने के बाद भी विमान को संभाला और 174 यात्रियों की जान को सुरक्षित रखा। विमान को सऊदी अरब के ताबुक में सुरक्षित उतारना कोई छोटी बात नहीं है। यह बहादुरी की मिसाल है।

संकट में संयम ही असली बहादुरी : कई लोग इस घटना के बाद पायलट की मानसिक और शारीरिक जांच की बात कर रहे हैं। जांच होना स्वाभाविक है और अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के नियमों के अनुसार जरूरी भी है, लेकिन जांच का अर्थ यह नहीं है कि हम उस बहादुरी पर सवाल उठाएं, जिसने सैकड़ों परिवारों को अनाथ होने से बचाया। सवाल उठाना आसान है, लेकिन उस ऊंचाई पर जब रक्त बह रहा हो और विमान तेजी से ऊंचाई खो रहा हो, तब विमान को संभालना कितना कठिन है, इसका अंदाजा जमीन पर बैठकर नहीं लगाया जा सकता। कैप्टन ने जो किया, वह पेशेवर क्षमता के साथ मानवीय जिम्मेदारी का सर्वोच्च उदाहरण है।

भारतीय पायलट पर पूरी दुनिया को गर्व : आज दुनिया में भारतीय पायलटों की मांग सबसे अधिक है। अमेरिका से लेकर

संकट में संयम, आसमान में भारत का गौरव



कई लोग इस घटना के बाद पायलट की मानसिक और शारीरिक जांच की बात कर रहे हैं। जांच होना स्वाभाविक है और अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के नियमों के अनुसार जरूरी भी है, लेकिन जांच का अर्थ यह नहीं है कि हम उस बहादुरी पर सवाल उठाएं, जिसने सैकड़ों परिवारों को अनाथ होने से बचाया।

ब्रिटेन में व्यवहार और तनाव पर भी नजर : ब्रिटेन की नागरिक विमानन प्राधिकरण की व्यवस्था में पायलट के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही तनाव से निपटने की क्षमता, काम और निजी जीवन

का दबाव, संबंधों से जुड़ी कठिनाइयां और परिचालन दल के साथ समन्वय जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। यदि किसी समस्या के संकेत मिलते हैं तो विशेषज्ञ मूल्यांकन की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य

मानसिक स्वास्थ्य की हर समस्या को खतरा मानना नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति की पहचान करना है, जो उड़ान सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसे बहादुरी पर सवाल के रूप में देखना अन्याय होगा।

ऑस्ट्रेलिया में बिना पूर्व सूचना जांच : ऑस्ट्रेलिया की नागरिक विमानन व्यवस्था में सुरक्षा संवेदनशील विमानन कर्मचारियों के लिए शराब और पदार्थों की जांच का स्पष्ट प्रावधान है। इसमें उड़ान दल के साथ केबिन क़ू रखरखाव कर्मचारी और अन्य सुरक्षा संवेदनशील भूमिकाएं शामिल हैं। नागरिक विमानन सुरक्षा प्राधिकरण बिना पूर्व सूचना के भी जांच कर सकता है। परीक्षण की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सुरक्षा संवेदनशील काम से हटाया जाता है और चिकित्सकीय मूल्यांकन तथा आवश्यक हस्तक्षेप की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह व्यवस्था बताती है कि दुनिया भर में सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन सुरक्षा का अर्थ पायलट का अपमान नहीं है।

अमेरिका में नियमित मेडिकल निगरानी : अमेरिका में संघीय विमान प्रशासन यानी एफएए के अनुसार एयरलाइन पायलटों को उनकी उड़ान की श्रेणी और उम्र के अनुसार नियमित मेडिकल परीक्षण से गुजरना होता है। यह अवधि छह महीने से पांच वर्ष तक हो

सकती है। मेडिकल प्रक्रिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी शामिल है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन कराया जाता है। यह व्यवस्था भी यही बताती है कि जांच और निगरानी एक सतत प्रक्रिया है, जो हर पायलट के लिए समान है। इसे किसी एक घटना से जोड़कर किसी कैप्टन की बहादुरी पर सवाल उठाना सही नहीं है।

भारत आज दुनिया में अपनी रक्षा प्रणाली से लेकर अपनी विमानन सेवा तक हर क्षेत्र में धूम मचा रहा है। जब भारत में बना ब्रह्मोस दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है, तब भारत का पायलट भी दुनिया में अपनी कुशलता का परचम लहरा रहा है। ऐसे समय में अपने ही नायक पर सवाल उठाना उचित नहीं है? कैप्टन ने जो किया, वह केवल एक नौकरी नहीं थी, वह मानवता की सेवा थी। उसने अपने धावों की परवाह किए बिना 174 लोगों को नया जीवन दिया। क्या यह बहादुरी नहीं है? क्या यह गौरव की बात नहीं है?

जांच और सम्मान दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जांच व्यवस्था का हिस्सा है और सम्मान बहादुरी का पुरस्कार है। हमें दोनों को अलग रखना चाहिए। कैप्टन की बहादुरी पर सवाल उठाना उस वर्दी पर सवाल उठाने जैसा है, जो हर दिन लाखों लोगों को सुरक्षित आकाश में पहुंचाती है। भारत का गौरव विश्व स्तर पर बढ़ाने वाले ऐसे पायलटों को हमें सिर-आंखों पर बिठाना चाहिए, न कि कठपुतरे में खड़ा करना चाहिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

यूपीआई से भुगतान पर शुल्क लगाने से सियासत और बवाल...

डॉ. विश्वास तिवारी

भारत में सफलता का रास्ता है ‘पहले लत लगाओं और फिर कमाओं’ किसी जमाने में लोगों को मुफ्त में चाय पिलाई जाती थी। कुछ दिनों बाद लोगों को उसकी लत लग गई और आज बिना चाय पिए लोगों की सुबह ही नहीं होती। इसी तरत कुछ वर्ष पहले मुफ्त मोबाइल डेटा देकर मोबाइल उपभोक्ताओं को ऐसा आकर्षित किया कि डेटा की जरूरत उनकी आदत बन गया। आज स्थिति यह है कि बिना डेटा के लोगों को भूख भी नहीं लगती है। फिर मुफ्त की होम डिलीवरी आई। पहले दरवाजे तक सामान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के घर तक पहुंचाया जाता था। देश के युवाओं को यह बहुत पसंद आया। जब लोगों को इसकी आदत लग गई तो धीरे-धीरे डिलीवरी शुल्क लगा दिया गया। जो सुविधा मुफ्त थी उस पर छोटा सा शुल्क लगा दिया गया। यही शुल्क कल ज्यादा ही हो सकता है। जो चीज मुफ्त मिलती है, उसकी आदत जल्दी लगती है, जो लोग बिना पर्स के घर से यूपीआई के भरोसे बाजार निकल जाते थे उन्हें अब पर्स लेकर चलना पड़ेगा।

सरकार द्वारा लिए गए फैसले से 15 अक्टूबर 2026 से यूपीआई भुगतान पर मामूली शुल्क लेने पर व्यापारियों का विरोध और विपक्ष द्वारा राजनीति शुरू हो गई है। यूपीआई यानि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली को शुरू हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। जब 2016 में यह शुरू हुआ था तब सिर्फ 44 बैंक इससे जुड़े थे। आज राष्ट्रीय बैंक,प्राइवेट बैंक ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को मिलाकर 700 से अधिक बैंक इससे जुड़े हैं। अब तक यह पूरी तरह मुफ्त था, इसलिए इसका चलन तेजी से बढ़ रहा था। आज देश में प्रतिदिन 66 करोड़ रुपये का लेनदेन यूपीआई के द्वारा हो रहा था। देश की 55 करोड़ आबादी के पास कोई न कोई यूपीआई पेप है। सरकार पर यूपीआई भुगतान पर शुल्क या एमडीआर लगाने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। पेमेंट्स कार्डसिल ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर जीरो एमडीआर पर फिर से विचार करने को कहा था। इसके सदस्यों में अमेजन पे, गूगल पे, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई पहले ही सरकार से इस नीति पर पुर्नविचार करने का अनुरोध कर चुके है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा था कि किसी न किसी को तो इसकी लागत उठानी ही पड़ेगी और अंतिम फैसला सरकार ही करेगी न कि केंद्रीय बैंक। उद्योग जगत के अनुसार यूपीआई के संचालन, सर्वर बैंड विथ, धोखाधड़ी रोकने की प्रणाली और बैंक का



टेक्निकल सपोर्ट बनाने की वार्षिक लागत 20 हजार करोड़ रुपये है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है। भारत सरकार का कहना है कि वह यूपीआई को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाना चाहती है, इसलिए उसने यूपीआई एमडीआर लगाने का फैसला किया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पर्सन-टू-पर्सन रुपये ट्रांसफर करने में कोई शुक्ल नहीं लिया जाएगा, किंतु 2000 रुपये से ऊपर की राशि पर भुगतान शुल्क लोगों के बजाए व्यापारियों को चुकाना होगा। यूपीआई भारत की एक ऐसी उत्कृष्ट प्रणाली है जिसने तत्काल भुगतान की परिभाषा ही बदल दी। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है। यह एक ऐसा मॉडल है, जिसके कारण भारत की गणना आज विश्व के सबसे बड़े तत्काल भुगतान के बाजार के शीर्ष पर होती है। स्मार्टफोन के माध्यम से किसी भी दो बैंक खातों के बीच रुपये का लेन-देन को तत्काल, सुविधाजनक और आसान बनाना एक नई क्रांति से कम नहीं था। आज सड़क किनारे बैठे किसी सब्जीवाले से लेकर नाई की दुकान या बड़े मॉल में क्यूआर कोड देखा जा सकता है।

कहने को तो यह शुल्क व्यापारियों से वसूला जाना है, लेकिन व्यापारी शुल्क का यह बोझ बड़ी चतुराई से आम लोगों पर शिफ्ट कर देंगे और हो सकता है यह उद्धेष्ट पता नहीं लगे। हालांकि व्यापारी संगठनों ने दिल्ली में सरकार से कहा है कि इस शुल्क का वहन वह स्वयं करेंगे और ग्राहकों से नहीं वसूलेंगे, लेकिन भारत में कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। चाहे वो राजनेता हो या अधिकारी। फिर ये तो कारोबारी है,जो पैसा कमाने के लिए ही काम करते है।

विपक्षी दल पेपर लोक, मंदिर में चढ़ावा चोरी और ई-20 पेट्रोल के बाद इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे है। राहुल गांधी ने तो यह तक कह दिया कि अब तक मुफ्त रहे यूपीआई पर शुल्क

अमेरिका केदबाव में लगाया गया है और इसका बोझ आम उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। कई देश पहले ही इसे अपना चुके है, उनमें चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, सिंगापुर, यूएई, मॉरीशस और श्रीलंका शामिल है और कई देश अपने यहां भुगतान के इस डिजिटल मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार को इस शुल्क के बारे आम जनता को विस्तार से बताना होगा, ताकि लोगों का भ्रम दूर हो सके। यह आम जनता पर कोई बड़ा बोझ नहीं है, लेकिन जब लोगों को, व्यापारियों को मुफ्त की आदत पड़ जाती है, तो वह कोई भी अतिरिक्त शुल्क का विरोध करती है। इस शुल्क की असली तस्वीर देखने के लिए हमें इसका अर्थशास्त्र और आंकड़ों को समझना होगा। इसमें 2000 रुपये तक के यूपीआई के भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। ज्यादातर लोग एक बार में इससे ज्यादा भुगतान नहीं करते है। सरकार का दवाव है कि 96 प्रतिशत लोगों का लेनदेन 2000 रूपये से कम का ही होता है।

जो भी दुकानदार जो एक महीने में एक लाख रूपये तक यूपीआई से लेते है, उन पर भी कई शुल्क नहीं लगेगा। इस का असर केवल बड़े व्यापारियों और दुकानदारों पर लगेगा। शुल्क की दर भी काफी कम है। वह भी सिर्फ .4 प्रतिशत है या 300 रुपये तक। इसमें कई जरूरी सेवाओं के लिए जैसे पेट्रोल पंप, रेल्वे टिकट, बिजली पानी का बिल, स्कूल कॉलेजों की फीस पर भी विशेष राहत दी गई है। यहां चाहे कितनी भी बड़ी रकम हो सिर्फ 5 रुपये का फ्लैट शुल्क ही लगेगा। जो लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करते है उससे यह 4 गुना तक कम होगा। सरकार अगर आम जनता और व्यापारियों को यह ठीक से समझाने में कामयाब हो जाएगी तो इतना विरोध नहीं होगा। 23 सितंबर को यूपीआई पर एमडीआर के विरोध में भोपाल और इंदौर में ‘नो यूपीआई डे’ मनाया गया और कारोबारियों ने सिर्फ नगद भुगतान में ही धंधा किया। बाकि देशों की तुलना में यह शुल्क काफी कम है। चीन में तो यह शुल्क .6 प्रतिशत लगता है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यूपीआई पर शुल्क लगाने से पिछले 8 माह से अपने चमच पर रही महंगाई और बढ़ सकती है। इसमें राशन से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी हो सकती है। विश्वभर में चल रहे युद्ध के कारण उर्वरक और कच्चा तेल लगातार महंगे हो रहे है। कृषि के क्षेत्र में भी निवेश कम हो रहा है तो ऐसे में क्या व्यापारी कोई भी नया शुल्क अपनी जेब से भरने को तैयार होगा?

सरकार को ध्यान रखना होगा, जिस ऑनलाईन भुगतान प्रणाली को दुनिया भर से सरहना मिल रही है, ऐसे में ये शुल्क कहीं महंगा सौदा न बन जाए।

एक समय था जब दुनिया भारत को हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार कहती थी और आज वही दुनिया भारत को हथियारों का भरोसेमंद विक्रेता कह रही है। यह बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं है, यह सोच का बदलाव है। रक्षा निर्यात ने जब 38,424 करोड़ का आंकड़ा पार किया तो यह संदेश गया कि भारत अब केवल अपनी सेना के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सेनाओं के लिए भी सोचता है। अस्सी से अधिक देशों तक भारतीय रक्षा उत्पाद पहुंच रहे हैं और निर्यातकों की संख्या 145 हो गई है। यह धूम किसी विज्ञापन से नहीं, बल्कि गुणवत्ता और भरोसे से पैदा हुई है।

ब्रह्मोस की गर्जना से गूँजा अंतरराष्ट्रीय बाजार : ब्रह्मोस नाम ही अब बाजार में ब्रांड बन गया है। छह सी मिलियन डॉलर से अधिक का सौदा कर इस मिसाइल ने बता दिया है कि भारतीय तकनीक किसी से कम नहीं है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो जमीन, समुद्र और हवा, तीनों से वार कर सकती है। फिलीपींस ने इसे अपनाया और अब वियतनाम और इंडोनेशिया भी कतार में हैं। रक्षा सचिव के अनुसार, ब्रह्मोस इस बदलती तस्वीर का प्रमुख उदाहरण बनकर उभरी है। जब कोई देश ब्रह्मोस खरीदता है तो वह सिर्फ मिसाइल नहीं खरीदता, वह भारत की प्रतिबद्धता खरीदता है कि संकट में भारत साथ खड़ा रहेगा।

आयातक से निर्यातक बनने की कहानी : कभी हम अपनी जरूरत का सत्तर प्रतिशत सामान विदेशों से लाते थे। हमारे पास पैसा था, लेकिन तकनीक उधार की थी। फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आया। सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोले, डीआरडीओ और निजी उद्योग ने हाथ मिलाया और खरीद में स्वदेशी को प्राथमिकता मिली। परिणाम यह हुआ कि वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र ने 17,353 करोड़ और सरकारी उपक्रमों ने 21,071 करोड़ का निर्यात

दुनिया के बाजार में **भारत की धूम**

जब भारत ने बेचना शुरू किया तो दुनिया ने खरीदना शुरू किया



किया। यानी सरकारी क्षेत्र में 151 प्रतिशत और निजी क्षेत्र में 14 प्रतिशत की वृद्धि। यह कहानी बताती है कि जब देश अपनी ताकत पर भरोसा करता है तो दुनिया भी उस पर भरोसा करती है।

क्यों दुनिया को पसंद आ रहा है भारतीय सामान? : अंतरराष्ट्रीय बाजार में हथियार बेचना केवल कीमत का खेल नहीं है। यह भरोसे का खेल है। बड़े देश हथियार बेचते समय कई शर्तें लगाते हैं, कई बार वे राजनीति भी करते हैं, लेकिन भारत की नीति अलग है। भारत हथियार के साथ सम्मान बेचता है, दबाव नहीं। यह बात छोटे देशों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। दक्षिण-पूर्व एशिया के देश, जो समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, वे भारत की तटीय रक्षा प्रणाली को अपनी सेना की शान बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कभी पीठ नहीं दिखाएगा। यही कारण है कि भारत की धूम है। नौजवानों के हाथों में नया भविष्य : इस धूम के पीछे हजारों युवा हाथ हैं, जो हैदराबाद, नागपुर और लखनऊ की फैक्ट्रियों में दिन-रात काम कर रहे हैं। उनके लिए यह आंकड़ा केवल रुपया नहीं है, यह उनके पसीने का सम्मान है। आज का इंजीनियर अब विदेश जाने का सपना नहीं देखता, वह भारत में रहकर दुनिया के लिए हथियार बनाना चाहता है। यह बदलाव रोजगार का भी है और गर्व का

टिकाऊ और भरोसेमंद बेचता है और यही भरोसा भारत को दो ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक रक्षा बाजार में नई ताकत बना रहा है। आगे का लक्ष्य और बड़ा है : अभी यह शुरुआत है। 38,424 करोड़ का रिकॉर्ड एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। मंजिल है पचास हजार करोड़ और फिर एक लाख करोड़। इसके लिए हमें अनुसंधान में निवेश को तीन गुना करना होगा, इंजन और चिप जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भर होना होगा और सरकारी प्रक्रियाओं को और तेज करना होगा। ब्रह्मोस ने रास्ता दिखाया है। अब तेजस, प्रचंड, आकाश और अन्य प्रणालियों को भी इसी रास्ते पर दुनिया में धूम मचानी है। वह दिन दूर नहीं जब भारतीय विमानवाहक भी दुनिया की नौसेनाओं की शान बनेंगे।

दुनिया के बाजार में भारत की धूम केवल व्यापार की धूम नहीं है। यह सम्मान की धूम है। यह संदेश है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है। भारत अपने दम पर अपनी और दुनिया की सुरक्षा कर सकता है। ब्रह्मोस की गर्जना ने यह संदेश दे दिया है कि भारत का समय आ गया है। यह समय गर्व करने का है और अधिक मेहनत करने का है, ताकि आने वाले वर्षों में हर महाद्वीप में भारत की तकनीक की धूम रहे।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

अरुणा शर्मा

पितृ पक्ष आता है तो हम बहुत शिदत से अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पंडित बुलाए जाते हैं, पिंडदान होता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है, तर्पण किया जाता है और हम कहते हैं कि हमारे पितर प्रसन्न होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। लेकिन एक सवाल, जो इस पूरे कर्मकांड के बीच कहीं खो जाता है, वह यह है कि जब हमारे माता-पिता जीवित थे, तब हमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था? आज लाखों बुजुर्ग वृद्धाश्रम, आश्रय गृह और सेवा सदन में रहने को मजबूर हैं। उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, फिर भी वे अनाथों की तरह जीवन काट रहे हैं। आखिर हम इतने निष्ठुर कैसे हो गए?

पेट काटकर पाला और हमने हाथ काटकर छोड़ा। जिस मां ने अपना पेट काटकर बच्चों को पाला, जिस पिता ने अपनी इच्छाओं को मार्कर बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और बड़ा किया, उसी मां-बाप को जब सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं। बचपन में जब बच्चा रात भर रोता था तो मां जागती थी, पिता कंधे पर लेकर घूमता था। तब कोई हिसाब नहीं था कि कितना खर्च हुआ, कितनी नींद खराब हुई। लेकिन जब वही मां-बाप बूढ़े होते हैं, उनकी आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनाई देता है, तो हम हिसाब लगाने लगते हैं कि इन पर कितना खर्च

पितृ पक्ष पर पिंडदान: जीवित माता-पिता का अपमान

हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। यह कैसा न्याय है? वृद्धाश्रमों की बढ़ती भीड़ क्या कहती है? पहले कहा जाता था कि वृद्धाश्रम में वे लोग रहते हैं, जिनका कोई नहीं होता, लेकिन आज हकीकत बदल गई है। आज वृद्धाश्रम में वे लोग ज्यादा हैं, जिनके बेटे विदेश में हैं, बड़ी नौकरी में हैं, बड़े घरों में रहते हैं। कई बुजुर्ग तो खुद बताते हैं कि घर में जगह की कमी नहीं थी, दिल में जगह की कमी हो गई थी। बहू को सास से परेशानी थी, बेटे को पिता की टोका-टोकी से परेशानी थी और धीरे-धीरे उन्हें समझा दिया गया कि आप वृद्धाश्रम में ज्यादा सुखी रहेंगे। वहां सेवा होगी, वहां आपके जैसे लोग मिलेंगे। यह कैसी सेवा है, जो अपनों से दूर कर दे?

हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जीवित माता-पिता की सेवा ही सबसे बड़ा श्राद्ध है, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। जीवित माता-पिता को हम वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और मरने के बाद उनके नाम पर बड़ा भोज करते हैं, फोटो पर माला लगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने अपने पिता के लिए इतना खर्च किया। यह कैसी श्रद्धा है, जो जीते जी नहीं दिखाई देती और मरने के बाद दिखावे में बदल जाती है? यदि मां-बाप भूखे रहे, प्यासे रहे,



अकेले रहे तो मरने के बाद हलवा-पूरी खिलाने से क्या आत्मा तृप्त होगी? आत्मा तो जीते जी तृप्त होती है, एक गिलास पानी देने से, एक मोठा बोल बोलने से।

हम निष्ठुर क्यों होते जा रहे हैं? इसका कारण एक नहीं है, कई कारण हैं। हमारी सोच में बदलाव आया है। हमने रिश्तों को भी लेन-देन बना दिया है। हम सोचते हैं कि मां-बाप ने जो किया, वह उनका कर्तव्य था, अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। दिखावा भी एक कारण है। हम बाहर की दुनिया में बहुत व्यस्त हो गए हैं, सोशल मीडिया में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन घर के बुजुर्गों के लिए समय नहीं है। सहनशक्ति की कमी, छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा और फिर अलग होने का चलन, बच्चों को बचपन से ही संस्कार न देना, हमने बच्चों को अंग्रेजी सिखाई, गणित सिखाया, कंप्यूटर सिखाया, लेकिन बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया। तो वही बच्चे बड़े होकर हमें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाते हैं।

बुजुर्ग हमसे धन नहीं मांगते, बड़ा घर नहीं मांगते। वे सिर्फ थोड़ा समय मांगते हैं, थोड़ा प्यार मांगते हैं। वे चाहते हैं कि शाम को कोई उनके पास बैठे, उनकी बात सुने, उनकी कहानी सुने। वे चाहते हैं कि परिवार में उनकी

मौजूदगी का एहसास रहे। उन्हें यह न लगे कि वे फालतू हैं। यदि हम इतना भी नहीं दे सकते तो हमारा शिक्षित होना किस काम का, हमारी तरक्की किस काम की?

पितृ पक्ष पर यदि सच में अपने पितरों को याद करना है तो एक संकल्प लीजिए कि अपने जीवित माता-पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे, उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। यदि आपके आसपास कोई बुजुर्ग वृद्धाश्रम में है तो महीने में एक बार उनसे मिलने जाइए, उनसे बात कीजिए। हो सके तो अपने घर के बुजुर्गों को वापस घर लाइए। सरकार को भी चाहिए कि वह ऐसे बेटों पर सख्त कानून लागू करे, जो सक्षम होते हुए भी माता-पिता को छोड़ देते हैं। लेकिन कानून से ज्यादा जरूरत संस्कार की है। जब आप पितृ पक्ष में अपने पितरों को याद कर रहे हों तो एक बार आंख बंद करके सोचिए कि क्या आपके माता-पिता आपके साथ हैं, क्या वे खुश हैं, क्या वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? यदि जवाब हां है तो आपका श्राद्ध सफल है। यदि जवाब नहीं है तो आपकी पिंडदान बेकार हैं, क्योंकि भूखे पेट को भोज नहीं, प्यार चाहिए और अकेले मन को मंत्र नहीं, साथ चाहिए। वृद्धाश्रम की दीवारों पर लिखी उदासी को मिटाना है तो हमें अपने घर के दरवाजे खोलने होंगे और दिल में जगह बनानी होगी। तभी पितृ पक्ष सार्थक होगा, तभी पूर्वजों की आत्मा सच में शांत होगी।